



दक्षिण भारत राष्ट्रमत



தக்ஷிண பாரதத் ராஷ்டிரமத் | தினமணி ஹிந்தி நாளிதழ் | चेन्नई और बंगलूरु से एक साथ प्रकाशित

5 'मयमुत कारोबार' का नया केंद्र बना उरप्रदेश : योगी

6 नेपाल के हिंसक विद्रोह की गहराई से पड़ताल आवश्यक

7 इमरजेसी के समय का माहौल मौने अपनी आँखों से देखा है : अनुपम

फ़र्ट टैक

ट्रंप ने टिकटों को लेकर सौदा होने का संकेत दिया... राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया साइट पर अपने एक पोस्ट में कहा है कि अमेरिका और चीन के अधिकारियों के बीच बैठक अच्छी रही और उस एक 'खास कंपनी' के संबंध में सौदा हो गया है जिसे हमारे देश के युवा बहुत हद तक बचना चाहते थे।

चीन ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति के लिए अपना गुप्त सैन्य परिसर खोला... पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली ज़रदारी को चीन में एक गुप्त सैन्य परिसर का दौरा कराया गया जहाँ उन्होंने संयुक्त रक्षा उत्पादन बढ़ाने की बात कही।

पंजाब में 385 करोड़ का फर्जी बिलिंग घोटाला उजागर... पंजाब के आबकारी एवं कराधान मंत्री हरपाल सिंह चौधरी ने सोमवार को कहा कि उनके विभाग ने 385 करोड़ रुपये के फर्जी लेनदेन से जुड़े घोटाले में कथित सिलसिले के खिलाफ दो प्राथमिकी दर्ज की हैं।

वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 पर रोक लगाने से उच्चतम न्यायालय का इनकार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों पर रोक लगा दी, जिनमें यह भी शामिल है कि केवल वे लोग ही किसी संपत्ति को वक्फ के रूप में दे सकते हैं जो पिछले पांच साल से इस्लाम का पालन कर रहे हैं।

प्रधान न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति आंगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने इस विधायक मुद्दे पर 128 पन्नों के अपने अंतरिम आदेश में कहा, 'पूर्व धारणा हमेशा कानून की संवैधानिकता के पक्ष में होती है और हस्तक्षेप केवल दुर्लभ से दुर्लभ मामलों में किया जा सकता है।'

पीठ ने कहा, 'हमें ऐसा नहीं लगता कि पूरे कानून के प्रावधानों पर रोक का कोई मामला बनता है। इसलिए, अधिनियम पर रोक के अनुरोध को खारिज किया जाता है।'

द इक्रीटीज' के लिए, न्यायालय जिलाधिकारी को वक्फ संपत्तियां तय करने के लिए दी गई शक्तियां सहित कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी तथा वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिम भागीदारी के मुद्दे पर आदेश जारी किया।

'बैलेंसिंग द इक्रीटीज' यह कानूनी सिद्धांत है, जिसके तहत न्यायालय विवाद में शामिल सभी पक्षों के संभावित लाभ और हानि के साथ-साथ व्यापक सार्वजनिक हितों को भी ध्यान में रखता है, ताकि यह निर्णय लिया जा सके कि निषेधाज्ञा जैसी न्यायसंगत राहत प्रदान की जाए या नहीं। पीठ ने केंद्रीय वक्फ परिषद को निर्देश दिया कि कुल 20 में से चार से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं होने चाहिए, और राज्य वक्फ बोर्डों में 11 में से तीन से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं होने चाहिए।

पीठ ने कहा, 'हमें ऐसा नहीं लगता कि पूरे कानून के प्रावधानों पर रोक का कोई मामला बनता है। इसलिए, अधिनियम पर रोक के अनुरोध को खारिज किया जाता है।'

धारा 3 के खंड (आर) का वह भाग जिसमें कहा गया है कि नामित अधिकारी द्वारा संपत्ति को सरकारी संपत्ति घोषित करने के मामले में, उसे राजस्व रिकॉर्ड में आवश्यक संशोधन करना होगा और राज्य सरकार को एक रिपोर्ट सौंपनी होगी।

न्यायालय ने कहा, 'जब तक संशोधित वक्फ अधिनियम की धारा 3 की तहत वक्फ संपत्ति के स्वामित्व से संबंधित मामले का, धारा 83 के तहत अधिकरण द्वारा शुरू की गई कार्यवाही में अंतिम रूप से निर्णय नहीं हो जाता, न तो वक्फ को संपत्ति से बेदखल किया जाएगा और न ही राजस्व रिकॉर्ड व वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में की गई प्रविष्टियां प्रभावित होंगी।'

अमित शाह 4,794 करोड़ के जब्त मादक पदार्थ नष्ट करेंगे... नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देश के विभिन्न हिस्सों से जब्त किए गए 4,794 करोड़ रुपये के मादक पदार्थों को नष्ट करने की प्रक्रिया मंगलवार को शुरू करेंगे।

एआई सुरक्षा को लेकर भारत ने प्रौद्योगिकी-विधिक दृष्टिकोण अपनाया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को कहा कि कृत्रिम मेधा (एआई) सुरक्षा को लेकर भारत ने एक प्रौद्योगिकी-विधिक दृष्टिकोण अपनाया है और सरकार का शुकाय नियमन से अधिक नवाचार की ओर है।

वैष्णव ने नीति आयोग की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, दुनिया के कई हिस्से एआई सुरक्षा को केवल कानूनी चुनौती मानते हैं और वे कानून बनाकर पारित कर लेने से यह मान लेते हैं कि एआई सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी। उन्होंने कहा, लेकिन भारत ने अलग दृष्टिकोण अपनाया है। हमारा एआई सेम्टी इंस्टीट्यूट एक वर्चुअल नेटवर्क है, जहां प्रत्येक बिंदु किसी एक विशिष्ट समस्या का समाधान कर रहा है।



मानते हैं और वे कानून बनाकर पारित कर लेने से यह मान लेते हैं कि एआई सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी। उन्होंने कहा, लेकिन भारत ने अलग दृष्टिकोण अपनाया है। हमारा एआई सेम्टी इंस्टीट्यूट एक वर्चुअल नेटवर्क है, जहां प्रत्येक बिंदु किसी एक विशिष्ट समस्या का समाधान कर रहा है।

शाह ने सोमवार को कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार भारत के सभी मादक पदार्थ-रोधी कार्य बल (एनटीएफ) को एकजुट करके मादक पदार्थों के खतरे को खत्म करने के लिए दृढ़ है। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया में 'एक्स' एक पोस्ट में कहा कि मादक पदार्थों को नष्ट करने की प्रक्रिया मंगलवार को यहां शुरू होने वाले एनटीएफ प्रमुखों के द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन में शुरू की जाएगी।

अमित शाह 4,794 करोड़ के जब्त मादक पदार्थ नष्ट करेंगे

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देश के विभिन्न हिस्सों से जब्त किए गए 4,794 करोड़ रुपये के मादक पदार्थों को नष्ट करने की प्रक्रिया मंगलवार को शुरू करेंगे।

उद्घाटन



प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को ऑपरेशन सिंदूर में अनुकरणीय भूमिका के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की सराहना की और राष्ट्र निर्माण में उनके महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डाला। रक्षा मंत्रालय के एक बयान में यह जानकारी दी गयी।

हिंदुओं के धर्मांतरण पर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या के बयान से बवाल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत dakshinbharat.com

बेंगलूरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या ने कहा है कि 'अगर हिंदू समुदाय में समानता होती, तो धर्मांतरण नहीं होता। उन्होंने कहा कि कुछ लोग व्यवस्था के कारण धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। अगर हिंदू समाज में समानता और समान अवसर होते, तो धर्म परिवर्तन क्यों होता? समाज में छुआछूत क्यों आई?'



कहा, कुछ लोग व्यवस्था के कारण धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। अगर हिंदू समाज में समानता और समान अवसर होते, तो धर्म परिवर्तन क्यों होता? समाज में छुआछूत क्यों आई? मुख्यमंत्रियों और ईसाइयों में असमानता के बारे में पूछे जाने पर सिद्धरामय्या ने आगे कहा, 'जहां कहीं भी असमानता है- चाहे वह मुसलमानों में हो या ईसाइयों में, न तो हमने और न ही भारतीय जनता पार्टी ने लोगों से धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा है। लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है। यह उनका अधिकार है। मुख्यमंत्री की इस टिप्पणी से विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी ने उन्हें मुसलमानों से समानता के मुद्दे पर सवाल उठाने की चुनौती दी है।

कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने हिंदू धर्म पर की गई इस टिप्पणी के लिए सिद्धरामय्या पर निशाना साधा। उन्होंने पूछा, 'जब समानता की बात आती है, तो आप हमेशा हिंदू धर्म को निशाना बनाते हैं... है ना मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या? क्या आपमें समानता के मुद्दे पर मुसलमानों से सवाल करने का साहस है?' भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष विजयेन्द्र येडीयुरप्पा ने कहा कि सिद्धरामय्या ने राजनीतिक विचारधारा केवल हिंदू धर्म और हिंदू रीति-रिवाजों को बंदनाम करने और अन्य धर्मों के अनुयायियों को खुश करने के लिए है। यह उनका अधिकार है।

सरकार का पांच साल में वाहन क्षेत्र को शीर्ष पर पहुंचाने का लक्ष्य : गडकरी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को कहा कि सरकार अगले पांच साल में भारत के वाहन उद्योग को दुनिया में शीर्ष पर पहुंचाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने 'अंतरराष्ट्रीय मूल्य शिखर सम्मेलन 2025' का उद्घाटन करते हुए कहा कि वाहन क्षेत्र सरकार को सबसे अधिक जीएसटी राजस्व देता है और रोजगार के अवसर पैदा करता है।



गडकरी ने बताया कि देश में दुनिया की सभी बड़ी वाहन कंपनियां मौजूद हैं। उन्होंने कहा, 'जब मैंने परिवहन मंत्री का कार्यभार संभाला था, तब भारतीय वाहन उद्योग का आकार 14 लाख करोड़ रुपये था। अब भारतीय वाहन उद्योग का आकार 22 लाख करोड़ रुपये है।'

इस समय अमेरिकी वाहन उद्योग का आकार 78 लाख करोड़ रुपये है। उसके बाद चीन (47 लाख करोड़ रुपये) और भारत (22 लाख करोड़ रुपये) का स्थान है। मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का सपना भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। उन्होंने कहा, 'हमें इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अछूता बुनियादी ढांचा विकसित करना होगा।'

आईडब्ल्यूटी के तहत आने वाली नदियों का पानी भारत की ओर मोड़ने के लिए सभी प्रयास जारी : पाटिल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल ने सोमवार को कहा कि सरकार भारतीय राज्यों में पानी की कमी को पूरा करने के लिए निरालिख सिंधु जल संधि के तहत आने वाली नदियों का पानी मोड़ने के लिए हठ संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले के अंतरराष्ट्रीय निहितार्थ हैं, इसलिए

हम हठसंभव प्रयास कर रहे हैं ताकि बहुत जल्द इस पानी को मोड़ा जा सके और हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लिए गए निर्णय और गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की भागीदारी से लागू किया जा रहा है। इससे देश को बड़ा लाभ होगा।

पाटिल ने आधार इंफ्रा कॉन्फ्लुएंस 2025 के दौरान एक सत्र को संबोधित करते हुए कहा, हालांकि उन्होंने उल्लेखनीय है कि 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों के हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था।

नदियों के पुनरुद्धार पर अपनी बात रखते हुए, पाटिल ने नवीन गंगे कार्यक्रम की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि कुंभ के दौरान लगभग 60-70 लाख श्रद्धालुओं के पवित्र स्नान के बावजूद, अपशिष्ट जल के उपचार के कारण नदी स्वच्छ बनी रही।

रिटर्न दाखिल करने के अंतिम दिन उपयोगकर्ता हुए परेशान

दक्षिण भारत राष्ट्रमत dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तारीख होने का कारण कर विभाग के पोर्टल पर सोमवार को बड़ी संख्या में लोगों ने लॉगइन किया। इस कारण उपयोगकर्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ा और उन्होंने सोशल मीडिया पर गड़बड़ियों की शिकायत की।

बड़ी संख्या में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने आईटीआर दाखिल करने की समयसीमा 15 सितंबर से आगे बढ़ाने की मांग की। दूसरी ओर विभाग ने कहा कि पोर्टल ठीक से काम कर रहा है और व्यक्तियों,

आयकर विभाग ने बड़ाया 16 सितंबर तक समयसीमा बड़ी संख्या में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने आईटीआर दाखिल करने की समयसीमा 15 सितंबर से आगे बढ़ाने की मांग की।

पिछले कुछ दिनों में कई चार्टर्ड अकाउंटेंट और अन्य लोगों ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि आयकर पोर्टल पर कर भुगतान और एआईएस (वार्षिक सूचना विवरण) डाउनलोड करते समय गड़बड़ियां आ रही हैं। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने सोमवार को यह भी शिकायत की कि वे ई-फाइलिंग पोर्टल में लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं।

दूसरी ओर आयकर विभाग ने स्पष्ट किया कि आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर है और इसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। विभाग ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर चल रही खबरों के विपरीत उसने आयकर रिटर्न (आईटीआर) भरने की अंतिम तारीख को आगे नहीं बढ़ाया है।

आयकर विभाग ने 'एक्स' पर पोस्ट में सोशल मीडिया पर प्रसारित एक बयान को फर्जी करार दिया, जिसमें कहा गया था कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दी गई है। विभाग ने करदाताओं से

किसी भी सूचना के लिए केवल खपलेशास्करूपकवर हेंडल पर भरोसा करने का अनुरोध किया। विभाग ने कहा, 'आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 ही है।' आयकर विभाग ने सोमवार सुबह ऐसी ही एक पोस्ट के जवाब में कहा, 'ई-फाइलिंग पोर्टल ठीक काम कर रहा है। कृपया अपना ब्राउजर साफ करें या किसी दूसरे ब्राउजर से पोर्टल पर पहुंचने को कोशिश करें।' आयकर विभाग ने कहा कि करदाताओं को आईटीआर दाखिल करने, कर भुगतान और अन्य संबंधित सेवाओं में मदद के लिए उसकी हेल्पडेस्क लगातार काम कर रही है, और फोन, लाइव चैट, वेबएक्स सत्र और एक्स के जरिये करदाताओं की मदद की जा रही है।

16-09-2025 17-09-2025
सूर्योदय 6:09 बजे सूर्यास्त 5:57 बजे

BSE 81,785.74 (-118.96)
NSE 25,069.20 (-44.80)

सोना 11,081 रु. (24 रु.) प्रति ग्राम
चांदी 136,000 रु. प्रति किलो

निशान मंडेला
दक्षिण भारत राष्ट्रमत
दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी पत्रिका
epaper.dakshinbharat.com

केलाश मण्डेला, नो. 9828233434
घात-प्रतिघात
अब फिर चुनाव के चक्कर में, लो नौद उड़ गई रातों की। कर रहे आज मनमानी सब, सुन-सुन मनचाही बातों की। बन गए मोहरे नेतागण, चार्लें सिर्फ बिसातों की। कर रहे सभी छुप कर हमले, हो रही सियासत घातों की।

